डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 1 जनवरी, 2026, डिस्पेच दिनांक 1 जनवरी, 2026

| वर्ष 69 | अंक 15 | भोपाल | 1 जनवरी, 2026 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

मंत्री श्री सारंग ने पांढुर्णा के बोरगांव स्थित सेवा सहकारी समिति का किया औचक निरीक्षण

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने जिला पांढुर्णा प्रवास के दौरान बोरगांव स्थित सेवा सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने समिति के प्रशासकीय कार्यों का विस्तार से अवलोकन किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण में लेखाकार द्वारा किए जा रहे संतोषजनक कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। वहीं समिति के प्रबंधक को सीपीपीपी (को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के माध्यम से नए व्यवसायिक अवसर सृजित करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बोरगांव क्षेत्र में व्यवसाय की अपार संभावनाएं हैं। सहकारिता विभाग के नवाचार सीपीपीपी के तहत औद्योगिक कंपनियों के साथ साझेदारी के अवसर तलाशे जाएं, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकें। उन्होंने कहा कि सीपीपीपी सहकारिता को सशक्त करने और पैक्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है।

मंत्री श्री सारंग ने सहकारिता विभाग के नवाचार सीपीपीपी के माध्यम से औद्योगिक कंपनियों के साथ साझेदारी के अवसर खोजने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीपीपीपी एक ऐसा आयाम है, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मंत्री श्री सारंग के इस दौरे से सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक संदेश गया है। निरीक्षण के बाद मंत्री श्री सारंग ने सुरुचि मसाला के प्रबंधक के साथ बैठक कर किसानों की आय बढ़ाने एवं पैक्स को नए व्यवसायिक अवसरों से जोड़ने को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि किसानों से कच्चा माल क्रय कर उसे सुरुचि मसाला जैसी कंपनियों को उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं का चयन कर पैक्स को नए व्यवसायों से जोड़ने की दिशा में कार्य करने पर बल दिया गया।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और इस दिशा में ठोस व व्यावहारिक प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।

आरसीएस कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण जल्द हो : श्री सारंग

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रदेश के पंजीयक सहकारी संस्थायें (आरसीएस) कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि 28 दिसम्बर तक आईटी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने की केन्द्र प्रायोजित परियोजना के तहत विभिन्न घटकों को जल्द सिंक्रोनाइज करें।

बताया गया कि पंजीयक कार्यालय मुख्यालय सहित प्रत्येक जिला कार्यालय, संभागीय कार्यालय के लिये हार्डवेयर क्रय किये जा चुके है। पंजीयक कार्यालय के कम्प्यूटराईजेशन के लिये

एक एकीकृत डिजीटल प्लेटफार्म MPSEDC द्वारा विकसित किया जा रहा है। बैठक में आयुक्त सहकारिता श्री मनोज पुष्प, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता और उप सचिव श्री मनोज सिन्हा सहित सहकारिता विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

डेयरी क्रांति की ओर मध्यप्रदेश का बड़ा कदम है डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादकों को हर संभव तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने सहित वर्तमान डेयरी उद्योग को सुनियोजित, सुव्यवस्थित, व्यावसायिक और लाभकारी बनाने की दिशा में 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना' आरंभ की है। यह योजना खासतौर पर उन जरूरतमंद युवाओं, किसानों और पशुपालकों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है, जो आधुनिक डेयरी इकाई स्थापित कर अपनी आय का स्थायी साधन विकसित करना चाहते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये-नये अवसर सृजित करना और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना में लाभार्थियों को 25 दूधारू पशुओं की एक इकाई स्थापित करने का अवसर दिया जाता है। इच्छुक और सक्षम हितग्राही अधिकतम 8 इकाइयां अर्थात 200 पशुओं तक की डेयरी परियोजना भी स्थापित कर सकते हैं। यह योजना छोटे से लेकर मध्यम स्तर के डेयरी उद्यमियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। योजना की एक प्रमुख शर्त यह है कि प्रति इकाई के लिए इच्छुक हितग्राही के पास कम से कम 3.50 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध हो। भूमि की यह व्यवस्था पशुओं के आवास, चारे की व्यवस्था और डेयरी के समुचित तरीके से संचालन के लिए जरूरी है। इसके साथ ही सरकार पशुपालकों/दूध उत्पादकों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग को भी महत्व दे रही है, जिससे पशुपालक वैज्ञानिक और आधुनिक पद्धति से अपना डेयरी बिजनेस चला सकें। पशुपालकों को आर्थिक सहायता देना इस योजना का सबसे आकर्षक पहलू है। परियोजना की कुल लागत पर सरकार द्वारा अनुदान (सब्सिडी) भी दिया जा रहा है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 33 प्रतिशत तथा अन्य सभी वर्गों को 25 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। शेष राशि बैंक ऋण के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रावधान से बड़े निवेश की बाधा काफी हद तक कम हो जाती है और डेयरी बिजनेस शुरू करना भी आसान हो जाता है। योजना में लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और चयन सामान्यत: "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर ही किया जा रहा है। साथ ही उन पशुपालकों को भी प्राथमिकता दी जा रही है, जो पहले से ही किन्हीं दुग्ध संघों या सहकारी संस्थाओं को निरंतर दुग्ध आपूर्ति कर रहे हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। इच्छुक आवेदक पशुपालन एवं डेयरी विभाग के आधिकारिक पोर्टल या अपने जिले के पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय से विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन भी ले सकते हैं।

योजना के बारे में कुछ तथ्य

1. मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में नवीन घटक के रूप में राज्य सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना को मंजूरी दी।
2. योजना के अंतर्गत 25 दुधारु पशु की प्रति इकाई राशि 36 लाख से 42 लाख रुपये तक की इकाई लागत है।
3. योजना में अधिकतम 8 इकाइयों की स्थापना एक हितग्राही द्वारा की जा सकती है। एक इकाई में एक ही नस्ल के गौ-वंश एवं भैसवंशीय पशु रहेंगे।
4. हितग्राही के पास प्रत्येक इकाई के लिये न्यूनतम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होना जरूरी है।
5. भूमि के लिये परिवार के सामूहिक खाते भी सम्मिलित हैं। इनके लिये अन्य सदस्यों की सहमति भी जरूरी होगी।
6. इकाइयों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से न्यूनतम कृषि भूमि की अर्हता में भी आनुपातिक वृद्धि जरूरी होगी।
7. पात्र हितग्राही को ऋण राशि का भुगतान चार चरणों में किया जायेगा।

गुना कलेक्टर की उपस्थिति में एक दिवसीय SOFTCOB (नाबार्ड योजना) प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न

गुना, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के मार्गदर्शन में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव द्वारा नाबार्ड प्रायोजित SOFTCOB योजना अंतर्गत बी-पैक्स कार्मिकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला गुना में किया गया।

कार्यक्रम में जिले भर की सहकारी समितियों से आए समिति प्रबंधकों एवं कार्मिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि गुना कलेक्टर श्री किशोर कल्याण जी, विशिष्ट अतिथियों एवं व्याख्याताओं द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, गुना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं स्टाफ द्वारा अतिथि व्याख्याताओं का पुष्पमालाओं एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

प्रशिक्षण सत्रों के दौरान SOFT-COB योजना के उद्देश्यों, सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, बी-पैक्स की कार्यप्रणाली, वित्तीय अनुशासन तथा क्षमता संवर्धन से संबंधित विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। अतिथि व्याख्याताओं ने सहकारी संस्थाओं को व्यावसायिक रूप से सशक्त बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने पर विशेष बल दिया।कार्यक्रम में उपायुक्त सहकारिता गुना श्री मुकेश कुमार जैन, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक गुना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री पी.के. परिहार सत्र समन्वयक SOFTCOB भोपाल, जिला सहकारी संघ प्रबंधक गुना एवं अशोकनगर, श्री हृदेश कुमार जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव सहित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुख्यालय गुना का स्टाफ उपस्थित रहा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए इसे अत्यंत उपयोगी एवं व्यवहारिक बताया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ नाबार्ड प्रायोजित यह एक दिवसीय SOFTCOB प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

बी-पैक्स कार्मिकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिवपुरी में सम्पन्न

शिवपुरी | मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के निर्देशन में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव द्वारा नाबार्ड प्रायोजित SOFTCOB (सॉफ्टकाब) योजना अंतर्गत बी-पैक्स (B-PACS) कार्मिकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यशाला 18 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास कार्यालय, जिला शिवपुरी में संपन्न हुई। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के कार्मिकों को नवीन नीतियों, प्रबंधन दक्षता एवं बहुउद्देशीय कार्यप्रणाली के प्रति सक्षम बनाना रहा। कार्यक्रम के प्रथम दिवस जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शिवपुरी के फील्ड अधिकारी श्री राकेश भदौरिया द्वारा उपस्थित सभी अतिथि व्याख्याताओं का पुष्प मालाओं एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। इसके पश्चात सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव के प्राचार्य श्री शिरीष पुरोहित द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ की प्रमुख गतिविधियों, सहकारी आंदोलन की भूमिका, साथ ही साइबर अपराध, डिजिटल लेन-देन में सावधानियाँ एवं साइबर सुरक्षा के उपायों पर विस्तार पूर्वक व्याख्यान दिया गया, जिसे प्रतिभागियों ने अत्यंत उपयोगी बताया। इसके उपरांत भोपाल से पधारे SOFT-COB सत्र समन्वयक श्री पी.के. परिहार द्वारा बी-पैक्स की नवीन उपविधियों, कार्यक्षेत्र विस्तार, प्रशासनिक सुधार एवं वित्तीय पारदर्शिता विषय पर गहन जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने पैक्स को आत्मनिर्भर एवं लाभकारी संस्था के रूप में विकसित करने हेतु व्यावहारिक सुझाव भी साझा किए। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव के जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री हृदेश कुमार द्वारा सहकारिता में नवाचार, आय सृजन के नए अवसर, तथा पैक्स को बहुउद्देशीय संस्था के रूप में विकसित करने पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात SOFTCOB सत्र समन्वयक श्री पी.के. परिहार ने राष्ट्रीय सहकारी नीति एवं राज्य सहकारी नीति की प्रमुख विशेषताओं, उद्देश्यों तथा उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन पर मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में आयोजित मूल्यांकन परीक्षा उपरांत प्रशिक्षार्थियों से फीडबैक लिया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत ज्ञानवर्धक, व्यवहारिक एवं समयानुकूल बताया तथा आगामी माह में पुनः ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया। समापन अवसर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शिवपुरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.एस. भदौरिया द्वारा सभी पैक्स एवं बैंक कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल एवं सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव के प्रति आभार व्यक्त किया गया। समापन सत्र में मुख्य रूप से सुश्री कु. दिव्यांशी तोमर, लेखाधिकारी (मुख्यालय), श्री विजय कुमार जैन, प्रभारी विपणन, शिवपुरी, श्री रुद्रकुमार पुरोहित, लेखाकक्ष, श्री सचिन कुमार सिंघल, शाखा प्रबंधक, शिवपुरी, इफको शिवपुरी के फील्ड अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुख्यालय शिवपुरी का स्टाफ एवं जिले की विभिन्न सहकारी समितियों से आए समिति प्रबंधक एवं कार्मिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंततः नाबार्ड प्रायोजित यह दो दिवसीय SOFTCOB प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हुआ।

तराना में सहकारी बैंक कार्मिकों का दो दिवसीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण संपन्न

उज्जैन, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित, उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में तराना तहसील अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, उज्जैन की शाखाओं में कार्यरत शाखा प्रबंधकों, समिति प्रबंधकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए दो दिवसीयकौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमका आयोजन किया गया।कार्यक्रम में संभाग आयुक्त श्री ए.के. सिंह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि सहकारी संस्थाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं तथा इनके कार्मिकों का दक्ष एवं तकनीकी रूप से सक्षम होना समय की आवश्यकता है।विशेष अतिथियों में सहायक आयुक्त श्री संजय कौशल, ऑडिट अधिकारी श्री संजीव शर्मा, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ प्रशिक्षण केंद्र इंदौर के प्राचार्य श्री दिलीप मरमट, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व डायरेक्टर, जिला पंचायत सदस्य एवं बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।प्रशिक्षण सत्रों में सहकारी बैंकिंग की कार्यप्रणाली, वित्तीय अनुशासन, डिजिटल बैंकिंग, ऑडिट प्रक्रिया, नेतृत्व विकास एवं ग्राहक सेवा जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया।कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों ने प्रतिभागियों के सक्रिय सहयोग की सराहना करते हुए इस प्रकार के प्रशिक्षणों को सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यक बताया।

एक दिवसीय SOFTCOB प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न

ग्वालियर। नाबार्ड द्वारा प्रायोजितSOFTCOB (Scheme of Financial Assistance for Training of Cooperative Banks Personnel) योजना के अंतर्गतबी-पैक्स (PACS) कार्मिकों के क्षमता संवर्धन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के निर्देशानुसार सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव द्वारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अपैक्स बैंक, सिटी सेंटर शाखा, ग्वालियर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं व्याख्याता श्री के.डी. सिंह, डी.आर.सी.एस., ग्वालियर, श्री हिमांशु खांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर तथा श्री पी.के.एस. परिहार, SOFTCOB सत्र समन्वयक, भोपाल द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलनके साथ किया गया। इस अवसर परजिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, ग्वालियर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अतिथि व्याख्याताओं का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।प्रशिक्षण सत्रों में अतिथि व्याख्याताओं द्वाराSOFTCOB योजना के उद्देश्य, सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली, वित्तीय अनुशासन, बैंकिंग प्रक्रियाएँ तथा बी-पैक्स कार्मिकों की भूमिका एवं दायित्वों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया।कार्यक्रम में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव के प्रशिक्षक श्री हृदेश कुमार राय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुख्यालय, ग्वालियर का स्टाफ, एवं विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से आए समिति प्रबंधक एवं कार्मिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

जिला भिण्ड में सॉफ्टकाब प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न

भिण्ड, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के निर्देशन में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव द्वारा नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकाब (SOFTCOB) योजनाके अंतर्गत बी-पैक्स (PACS) कार्मिकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुख्यालय, भिण्ड में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं व्याख्याता श्री मेहुल पवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक भिण्ड, श्री जे.पी. सगर, स्थापना प्रभारी, मुख्यालय भिण्ड, श्री जी.एस. नरवरिया, शाखा प्रबंधक, ऊमरी, श्री पी.के.एस. परिहार, सॉफ्टकाब सत्र समन्वयक, भोपाल एवं श्री शिरीष पुरोहित, प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक भिण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सभी अतिथि व्याख्याताओं का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अतिथि व्याख्याताओं द्वारा सॉफ्टकाब योजना के उद्देश्य, सहकारी बैंकिंग प्रणाली, बी-पैक्स की कार्यप्रणाली, कार्मिकों की भूमिका, वित्तीय अनुशासन एवं सेवा गुणवत्ता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव से प्रशिक्षक श्री हृदेश कुमार द्वारा प्रशिक्षण सत्र का संचालन किया गया। प्रशिक्षण में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक भिण्ड के अधिकारी-कर्मचारी एवं जिले की विभिन्न प्राथमिक सहकारी समितियों से आएसमिति प्रबंधकोंने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बताते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के सॉफ्टकाब क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

सहकारी बैंकों पर लागू कराधान पर कार्यशाला किसानों की सेवा करना सौभाग्य की बात

भोपाल :अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने सहकारी बैंकों पर लागू कराधान पर एक दिवसीय कार्यशाला कहा कि किसानों की सेवा करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। सेवा के लिए ज्ञान अर्जित करें और विशेषज्ञता प्राप्त करें। वे आज अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कालेज, भोपाल में प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे।

नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री सुरेश कुमार साहू, उप महाप्रबंधक नन्दू नायक,अपेक्स बैंक के प्राचार्य श्री पी.एस.तिवारी, वि.क.अ श्री अरुण मिश्र, उप महाप्रबंधक श्री के.टी. सज्जन, सहायक महाप्रबंधक श्री अरविंद बौद्ध, विषय विशेषज्ञ श्री अमूल राहंणेकर, चार्टर्ड अकाउंटंट उपस्थित थे।

श्री गुप्ता ने कहा कि हमारा प्रयास इस प्रशिक्षण संस्थान को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाने का है। हमारा प्रयास बेहतर माहौल व आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण में सभी को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसी कड़ी में आज इस कांफ्रेंस हाल का उद्घाटन हुआ है।

नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री सुरेश कुमार साहू ने प्रदेश में अल्पकालीन सहकारी संरचना को सुदृढ़ीकरण बनाने के प्रयास करने पर जोर दिया। आरंभ में अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कालेज के प्राचार्य श्री पी.एस.तिवारी अतिथियों का स्वागत एवं आयोजन की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के दूरदर्शी व सकारात्मक दृष्टिकोण व नाबार्ड के सहयोग से प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर व संख्या दुगनी होने में सफलता प्राप्त हुई है। नाबार्ड के लखनऊ स्थित संस्थान "बर्ड" ने "ए" एक्रिडेशन प्रदान किया है। आभार प्रदर्शन संकाय सदस्य श्री आर.के.दुबे ने किया।

दो दिवसीय सहकारी प्रदर्शनी का समापन

सीहोर। मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित, सीहोर के संयुक्त तत्वावधान में कृषि उपज मण्डी प्रांगण, सीहोर में आयोजित दो दिवसीय सहकारी प्रदर्शनी का समापन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ।

प्रदर्शनी का शुभारंभ सुधीर कैथवास, प्रभारी उप आयुक्त; सुनील सक्सेना, अंकेक्षण अधिकारी; मनोज शर्मा, प्रभारी कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक; कृपाल सिंह डुगारिया, जिला नोडल अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ जिला सीहोर; तथा तेज सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी संघ सीहोर द्वारा फीता काटकर एवं माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों का स्वागत मुख्य कार्यपालन अधिकारी तेज सिंह ठाकुर द्वारा पुष्पमालाओं से किया गया।

उद्घाटन पश्चात अतिथियों द्वारा भोपाल दुग्ध सहकारी संघ, बहुउद्देशीय महिला जागृति सहकारी संस्था रेहटी, काष्ठकला उद्योगी सहकारी संस्था बुधनी, बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था निपानियाकलां द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अतिथियों ने उत्पादों की गुणवत्ता, विपणन एवं संस्था विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं के अनुरूप सहकारिता के माध्यम से जन विकास एवं जन जागृति का कार्य किया जा रहा है।

प्रदर्शनी के दूसरे दिन श्रीमती महिमा शर्मा, मार्केटिंग ऑफिसर, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), भोपाल; भारत सिंह चौहान, प्रबंधक विपणन संस्था, सीहोर; एवं मुकेश भावसार, शाखा प्रबंधक, सहकारी बैंक शाखा मण्डी, सीहोर द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन कर उत्पाद विक्रेताओं से संवाद किया गया। समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सुधीर कैथवास, प्रभारी उप आयुक्त; सुनील सक्सेना, अंकेक्षण अधिकारी; रंजीत सिंह रैकवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विभाग जिला सीहोर; एवं तेज सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी संघ सीहोर उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी उपआयुक्त सुधीर कैथवास ने कहा कि सहकारी संस्थाओं के उत्पाद जनहित में अत्यंत उपयोगी एवं लाभदायक हैं। संस्थाओं को गुणवत्ता युक्त उत्पाद निर्माण पर निरंतर ध्यान देना चाहिए, जिससे सदस्यों के साथ-साथ संस्थाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि जिला सहकारी संघ मर्यादित, सीहोर द्वारा सहकारी प्रचार-रथ, सहकारी सम्मेलन, संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी के माध्यम से सहकारिता से जुड़ी शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाया जा रहा है। इसी क्रम में सहकारी प्रचार रथ द्वारा कृषि उपज मण्डी प्रांगण से प्रारंभ कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था पचामा होते हुए ग्राम खामलिया एवं नरेला में प्रचार-प्रसार किया गया, जो सराहनीय पहल है। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए जिला सहकारी संघ के प्रशासक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई एवं धन्यवाद दिया।

ग्रामीण विकास सहकारिता से संभव : अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

शाजापुर। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में जिला सहकारी संघ मर्यादित, शाजापुर के तत्वावधान तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गुलाना के सहयोग से सहकारिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेमराज सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष जिला पंचायत शाजापुर रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ युवा नेता योगेंद्र सिंह 'बंटी बना' ने की। कार्यक्रम में हीरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष भाजपा; सवाई सिंह, अध्यक्ष किसान संघ; बाबूलाल हावडिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष; एवं भाजपा नेताप्रकाश मेवाड़ा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन में योगेंद्र सिंह बंटी बनाने सहकारिता के माध्यम से किसानों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी तथा सहकारी संस्थाओं की बकाया राशि समय पर जमा करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। मुख्य अतिथि हेमराज सिंह सिसोदिया ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सहकारिता के माध्यम से ही संभव हैऔर सहकारी संस्थाएं किसानों की आर्थिक मजबूती की आधारशिला हैं। इस अवसर पर जिला सहकारी संघ द्वारा जिले केश्रेष्ठ किसान, ई-पैक्स (e-PACS) कंप्यूटरीकरण कर्मचारियों एवं श्रेष्ठ वसूली करने वाले संस्था प्रबंधकों को शाल, श्रीफल एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शब्बीर खान, प्रबंधक जिला सहकारी संघ द्वारा किया गया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर मांगीलाल जी एवं सवाई सिंह, अध्यक्ष किसान संघ सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग शाजापुर से मनोज श्रीवास्तव, बी.एस. भंवर; जिला सहकारी बैंक सलसलाई के प्रबंधक सुरेश शर्मा; जनपद सदस्य मांगीलाल सौराष्ट्र; सरपंच जीवन परमार सहित धर्मराज परमार, इंद्र सिंह परमार, रामबाबू परमार, रोशन मेवाड़ा, शाहिद तथा प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के प्रबंधक, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के कार्यक्रम में की सहभागिता ● सहकारी समितियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का किया अवलोकन

संस्थाओं को सुविधाओं से सशक्त और अपडेट करने की जरूरत : कलेक्टर

गुना। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर जिले की जिज्जी पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने सहभागिता की। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। आवश्यकता है कि सहकारी संस्थाओं को मल्टी-फैसिलिटी सुविधाओं से सशक्त किया जाए तथा उन्हें समयानुसार अपडेट रखा जाए, ताकि किसान और आमजन को अधिक लाभ मिल सके।

कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर श्री कन्याल ने सहकारिता सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेकर सहकारिता आंदोलन के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इसके पश्चात उन्होंने विभिन्न विभागों एवं सहकारी समितियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया।इस दौरान कृषि विभाग द्वारा कृषि नवाचारों, बीज एवं फसल उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। उद्योग विभाग द्वारा गुलाब, अमरूद, बेर सहित विविध कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। सांची दुग्ध उत्पाद, बीज समितियों के उत्पाद, बुनकर समिति चंदेरी द्वारा साड़ी एवं अन्य हस्तशिल्प वस्त्र उत्पादों की प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इसके साथ ही हस्तकरघा विभाग एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा जूट से निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कलेक्टर श्री कन्याल ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में कार्यरत युवा ब्रांच मैनेजरों को अपनी ऊर्जा, नवाचार एवं आधुनिक तकनीक के माध्यम से शासन की मंशा को समझते हुए कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सहकारिता क्षेत्र में बचत पर मिलने वाले अतिरिक्त लाभ की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।कार्यक्रम के समापन अवसर पर कलेक्टर द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सहकारी बैंकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष हेमंत सिंघार, संयुक्त आयुक्त सहकारिता एमपीएम भोपाल श्री बी.पी. सिंह, उप आयुक्त सहकारिता गुना श्री मुकेश कुमार जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी- कर्मचारी, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

साँची' में दूध संकलन 12 लाख लीटर के पार

दुग्ध उत्पादकों के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि

भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के मध्य हुए सहकार्यता अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (एमपीसीडीएफ), भोपाल से संबद्ध प्रदेश के 06 सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुंदेलखण्ड (सागर), ग्वालियर एवं जबलपुर द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम सेदैनिक दूध संकलन 12 लाख लीटर को पार कर गया है।

यदि मासिक आंकड़ों की बात करें तो दिसंबर माह में अब तक प्रतिदिन औसतन 11 लाख 32 हजार लीटर से अधिक दूध संकलन किया जा चुका है। यह उपलब्धि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में 'साँची डेरी' के निरंतर और सार्थक प्रयासों का परिणाम है।

मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने की दिशा में कदम

यह उपलब्धि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के उस संकल्प "मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश की राजधानी बनाना" को साकार करने की दिशा में एक ठोस और प्रभावी कदम मानी जा रही है। एनडीडीबी के सहयोग से प्रदेश की सहकारी दुग्ध संरचना को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

प्रबंध निदेशक ने दी बधाई

एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. संजय गोवाणी ने दूध संकलन 12 लाख लीटर के आंकड़े को पार करने पर 'साँची परिवार' के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलतादुग्ध उत्पादकों, सहकारी समितियों एवं फेडरेशन के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो पाई है।

डॉ. गोवाणी ने दुग्ध उत्पादकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारी समितियों से जुड़कर उन्होंने दूध संकलन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे दुग्ध उत्पादकों का 'साँची' ब्रांड के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह विश्वास भविष्य में भी बना रहेगा और सभी के सहयोग से मध्यप्रदेश को डेयरी क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जा सकेगा।

'सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका' विषय पर सहकारी सम्मेलन

पंचकूला, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हरियाणा के पंचकूला में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) द्वारा आयोजित "सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका" विषयक सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सहकारी संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे।सम्मेलन के दौरान मिल्क चिलिंग सेंटर, HAFED का आटा मिल, RuPay प्लेटिनम कार्ड, मॉडल पैक्स (PACS) का पंजीकरण तथा सहकारिता वर्ष के पोर्टल का लोकार्पण भी किया गया, जो देशभर में सहकारिता से जुड़ी जानकारियाँ किसानों तक पहुँचाने का कार्य करेगा।

हरियाणा कृषि और सहकारिता के सहयोग से रच रहा समृद्धि की नई कहानी

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा इतिहास, संस्कृति, धर्म और परंपराओं से समृद्ध प्रदेश है, जो आज कृषि और सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर आयोजित यह सम्मेलन देश में सहकारी आंदोलन को नई दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और बड़ी आबादी की आजीविका कृषि व पशुपालन पर आधारित है। यदि इन क्षेत्रों को संगठित रूप से सहकारिता से जोड़ा जाए तो यह केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक समृद्धि का माध्यम बन सकते हैं।

'सहकार से समृद्धि' प्रधानमंत्री मोदी का दूरदर्शी विज़न

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर 'सहकार से समृद्धि' का नया मंत्र देश को दिया है। इसका उद्देश्य किसानों को केवल सहायता पर निर्भर न रखकर उन्हें आत्मनिर्भर और लाभकारी व्यवस्था से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि पहले कृषि को केवल रोजगार के साधन के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसे आय बढ़ाने और समृद्धि का माध्यम बनाया जा रहा है।

अमूल मॉडल से समझाई सहकारिता की ताकत

श्री अमित शाह ने गुजरात की अमूल संस्था का उदाहरण देते हुए बताया कि आज अमूल से जुड़े लगभग 36 लाख दुग्ध उत्पादकों को प्रतिवर्ष करीब 90 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है, जबकि वही दूध सामान्य बाजार में बिके तो उसकी कीमत लगभग 12 हजार करोड़ रुपये ही होती। इस अंतर से सहकारिता की शक्ति स्पष्ट होती है। उन्होंने कहा कि कृषि, पशुपालन और सहकारिता — इन तीनों को जोड़कर ही वास्तविक रूप से "सहकार से समृद्धि" का निर्माण किया जा सकता है।

आधुनिक कृषि के तीन प्रमुख स्तंभ

श्री शाह ने कहा कि आज की कृषि नीति तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है—

1. कम पानी में अधिक उत्पादन, 2. कम रसायनों का उपयोग (प्राकृतिक खेती), 3. कम जोखिम वाली खेती

इसके अंतर्गत वैज्ञानिक सिंचाई, मृदा परीक्षण, जल संरक्षण, संस्थागत ऋण, बाजार तक पहुँच, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार सब्सिडी आधारित कृषि से आगे बढ़कर सस्टेनेबल और लाभकारी खेती को प्रोत्साहित कर रही है।

कृषि और ग्रामीण विकास बजट में ऐतिहासिक वृद्धि

केन्द्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2014 में कृषि बजट 22 हजार करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख 27 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण विकास बजट 80 हजार करोड़ से बढ़कर 1 लाख 87 हजार करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।

उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जिसे बीते 10 वर्षों में 10 से 25 करोड़ रुपये तक की विकास राशि प्राप्त न हुई हो।

किसानों के लिए चलाई जा रहीं प्रमुख योजनाएँ

सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं—

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (रु. 6,000 वार्षिक), • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, • कृषि अवसंरचना कोष (रु. 1 लाख करोड़), • ई-नाम प्लेटफॉर्म, • श्री अन्न मिशन, • दलहन–तिलहन मिशन, • डेयरी क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएँ, • 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा। इन पहलों से कृषि क्षेत्र को मजबूत आधार मिला है।

बालाघाट दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

बालाघाट। दुग्ध सहकारी समितियों को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बालाघाट जिले की दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले की विभिन्न दुग्ध सहकारी समितियों के अध्यक्ष, सचिव, प्रबंधक एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री वी. के. बर्वे, प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर द्वारा दुग्ध सहकारिता की अवधारणा, समिति प्रबंधन, लेखा-जोखा संधारण, दुग्ध संग्रहण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, लाभांश वितरण तथा शासन की सहकारी एवं दुग्ध विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

श्री बर्वे ने अपने उद्बोधन में कहा कि दुग्ध सहकारी समितियाँ ग्रामीण

अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो किसानों को नियमित आय, रोजगार और आत्मनिर्भरता प्रदान करती हैं। उन्होंने समितियों में पारदर्शिता, समयबद्ध लेखा परीक्षण एवं तकनीकी नवाचार अपनाने पर विशेष बल दिया।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताते हुए इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निरंतर आयोजन की आवश्यकता जताई।

खेल और सहकारिता में हुई अभूतपूर्व प्रगति : मंत्री श्री सारंग

भोपाल : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार की परिकल्पना जहाँ केंद्र और राज्य एक साझा लक्ष्य, साझा गति और साझा परिणाम के साथ काम करते हैं, आज मध्यप्रदेश में ज़मीन पर साकार रूप ले रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सक्षम नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने बीते दो वर्षों में सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। यह बात सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने अपेक्स बैंक समन्वय भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में कही।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग: प्रदेश का गौरव, देश में नई पहचान

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी आज राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदक अर्जित कर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। वर्ष 2024 में पेरिस (फ्रांस) में आयोजित ओलम्पिक व पैरा ओलम्पिक 2024 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रतिभागिता कर पदक अर्जित किये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्यप्रदेश ने खेलों में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तमिलनाडु में भी प्रदेश के खिलाड़ियों ने 29 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसी प्रकार 38वें नेशनल गेम्स, उत्तराखण्ड में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने 67 पदक अर्जित कर राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त किया।

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक तालिका में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ

वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल 57 पदक तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 391 पदक अर्जित किए। हॉकी एशिया कप 2025, 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर एवं एशियन केनो स्लालम चैंपियनशिप चीन में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश को शीर्ष राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया है।

प्रदेश के खिलाड़ियों ने बनाएं नये राष्ट्रीय रिकॉर्ड

प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर न केवल निरंतर पदक अर्जित कर रहे हैं, बल्कि नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर मध्यप्रदेश की खेल प्रतिभा को नई पहचान दिला रहे हैं। पोल वॉल्ट में देव मीणा ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रिकॉर्ड प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल स्पर्धा में रिकॉर्ड स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धि दर्ज की है। वहीं शॉट पुट में समरदीप सिंह ने अपने दमदार प्रदर्शन से राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कांस्य विजेता टीम में प्रदेश के 3 खिलाड़ी

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि तमिलनाडु में आयोजित एफआईएच जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप–2025 में भारतीय टीम ने अर्जेंटीना को 4–2 से पराजित कर पहली बार कांस्य पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस गौरवपूर्ण सफलता में मध्यप्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी, भोपाल के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंकित पाल, तलैम प्रियोबर्ता एवं थोनाओजाम इंगालेंबा लुवांग के उत्कृष्ट प्रदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

ओलम्पिक और एशियन गेम्स पदक विजेताओं को बनाएंगे राजपत्रित अधिकारी

खिलाड़ियों के सम्मान और भविष्य सुरक्षा पर सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र और लाइफटाइम अचीवमेंट जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। विक्रम पुरस्कार प्राप्त 28 खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दी गई है, वहीं ओलम्पिक और एशियन गेम्स पदक विजेताओं को राजपत्रित अधिकारी बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

खिलाड़ियों को दी गई सम्मान राशि

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को व्यापक प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले 1375 खिलाड़ियों को 116 लाख रुपये, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के 228 पदक विजेताओं को 153 लाख रुपये तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के 51 खिलाड़ियों को 37.83 लाख रुपये दिए गए। पेरिस ओलम्पिक 2024 में 3 कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 300 लाख रुपये एवं 3 प्रतिभागी खिलाड़ियों को 30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु 19 खेल संघ संस्थाओं को 50.80 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई।

क्रांति गौड़ को 1 करोड़ की सम्मान राशि

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की विजेता भारतीय महिला टीम की सदस्य प्रदेश की सुश्री क्रांति गौड़ को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गई है।

वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाने का लक्ष्य

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में 18 खेलों की 11 खेल अकादमियां संचालित हैं, जहाँ 1300 से अधिक खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेल अधोसंरचना के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होने बताया कि भोपाल के नाथू बरखेड़ा में लगभग 985 करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माणाधीन है। प्रदेश में 20 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सिंथेटिक टर्फ, 10 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक तथा 120 से अधिक स्टेडियम एवं खेल परिसर विकसित किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश को भारत का प्रमुख स्पोर्ट्स हब बनाना है।

खेल विभाग के नवाचार

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि युवाओं को शासन की योजनाओं से जोड़ने हेतु 'मेरा युवा मध्यप्रदेश' पोर्टल को सशक्त किया जा रहा है, जिस पर विभिन्न विभागों की युवा केंद्रित योजनाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 'खेलो बढ़ो अभियान' के माध्यम से विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं तथा युवाओं में खेलों के प्रति रुचि एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश युवा प्रेरक अभियान (MPYP) के अंतर्गत प्रदेश के सफल, सक्षम एवं प्रेरणादायी युवाओं को समाज के लिए मार्गदर्शक (मेंटोर) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

खेल विभाग की आगामी कार्ययोजना

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा लागू कर प्रतिवर्ष 10 सब-इंस्पेक्टर एवं 50 कांस्टेबल की नियुक्ति का प्रावधान किया जायेगा। मुख्यमंत्री खेल अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से इंडोर हॉल एवं आधुनिक खेल परिसरों का निर्माण प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देने हेतु विदेश भेजा जा रहा है तथा विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। 20वें एशियाई खेल 2026 तथा संभावित ओलम्पिक 2036 की तैयारियों के तहत विशेष प्रशिक्षण शिविर, टैलेंट सर्च कार्यक्रम, नई खेल अकादमियों एवं जिलावार फीडर सेंटर्स की स्थापना की जा रही है।

देश में पहली बार खेल विभाग एवं सभी खेल संघ मिलकर करेंगे यूथ गेम्स

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि देश में पहली बार सभी खेल विभाग और मान्यता प्राप्त खेल संघ मिलकर खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन करेंगे। खेलो एमपी यूथ गेम्स-2025- मध्यप्रदेश का ओलंपिक" 10 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि यूथ गेम्स में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भविष्य में राज्य टीम के चयन में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसमें पहली बार पारंपरिक खेलों और क्रिकेट को भी शामिल किया गया है।

देश में पहली बार स्किल एन्हेंसमेंट प्रोग्राम की शुरुआत

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के 'मन की बात' में उल्लेख के बाद शहडोल के 'मिनी ब्राजील' विचारपुर गाँव के फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्मनी के FC Ingolstadt 04 क्लब में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीक, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और प्रतिस्पर्धी अनुभव से जोड़ने के उद्देश्य से देश में पहली बार स्किल एन्हेंसमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत जहां प्रदेश के खिलाड़ियों को विदेशों में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा, वहीं विदेशी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मध्यप्रदेश की खेल अधोसंरचना, अकादमियों और खेल सुविधाओं से अवगत कराया जाएगा, जिससे आपसी अनुभव साझा कर प्रदेश की खेल प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल सके।

हर विधानसभा में खेल परिसर

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक एवं बहुउद्देशीय खेल परिसरों के निर्माण को सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन खेल परिसरों में विभिन्न खेलों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएँ, खिलाड़ियों के लिए अभ्यास एवं प्रतियोगिता के उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा और प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत आधार प्राप्त होगा।

स्पोर्ट्स टूरिज्म से बढ़ेगा जीडीपी में योगदान

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और जीडीपी में उल्लेखनीय योगदान बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि खेल आयोजनों, प्रशिक्षण शिविरों और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के माध्यम से पर्यटकों की आवक बढ़ेगी, जिससे होटल, परिवहन, स्थानीय व्यवसाय और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही खेल अधोसंरचना के विकास से निवेश आकर्षित होगा और मध्यप्रदेश को खेल एवं पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में नई पहचान मिलेगी।

सहकार से समृद्धि की दिशा में निरंतर अग्रसर प्रदेश

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 34.42 लाख किसानों को 21,493 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया। जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 1,550 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 2025-26 हेतु राज्य शासन द्वारा 694 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नवीन पैक्स, दुग्ध एवं मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से किसानों को पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

नवीन PACS, दुग्ध एवं मत्स्य सहकारी संस्थाओं का गठन

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि सहकार से समृद्धि अभियान के अंतर्गत 656 नवीन PACS, 758 दुग्ध एवं 203 मत्स्य सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया। नवीन संस्थाओं को भूमि, कार्यालय, गोदाम और प्रबंधकीय सहायता प्रदान कर सहकारी नेटवर्क को मजबूत किया गया है। प्रदेश देश में अग्रणी बनाते हुए 4536 PACS का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। ई-PACS के माध्यम से किसानों को ऑनलाइन सेवाएं और SMS के जरिए लेन-देन की सूचना उपलब्ध कराई जा रही है।

कमजोर जिला सहकारी बैंकों का सुदृढ़ीकरण

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि 38 में से 15 जिला सहकारी बैंकों के कमजोर होने के कारण किसानों को ऋण वितरण में कठिनाई थी। राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 6 जिला बैंकों को 300 करोड़ रुपये की

विकसित भारत का कृषि मॉडल : गौ-आधारित प्राकृतिक खेती और स्वस्थ जीवन

भोपाल : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विकास के उस मार्ग पर अग्रसर है, जहाँ आर्थिक प्रगति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सांस्कृतिक मूल्यों को समान महत्व दिया जा रहा है। इसी समग्र दृष्टि के अंतर्गत भारतीय कृषि को भी एक नए युग की ओर ले जाया जा रहा है। कृषि सदियों से हमारी सभ्यता की रीढ़ रही है। आधुनिक युग में रासायनिक उर्वरकों और सिंथेटिक कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता ने खेती की लागत बढ़ाने के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता, उसकी जलधारण क्षमता और दीर्घकालिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप, हमारे भोजन की गुणवत्ता और नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत की समस्याओं का समाधान हमारी अपनी परंपराओं और ज्ञान प्रणाली में निहित है। इसी विचार से प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है, जो भारतीय कृषि की मूल आत्मा से जुड़ी हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि को केवल उत्पादन के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के व्यापक संदर्भ में देखा जाए।

भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था सह-अस्तित्व और संतुलन पर आधारित रही है, जिसमें गौमाता की भूमिका केंद्रीय रही है। गौ केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादकता और पोषण सुरक्षा का आधार रही हैं। हमारे पूर्वज जानते थे कि गौवंश का संरक्षण सीधे मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ा है। गोबर और गोमूत्र से भूमि को पोषण मिलता है, सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं और मिट्टी पुनः जीवंत होती है। स्वस्थ मिट्टी से प्राप्त अन्न अधिक पौष्टिक, सुरक्षित और मानव शरीर के अनुकूल होता है।

प्राकृतिक खेती कृषि तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति

प्रधानमंत्री मोदी जी की दृष्टि में प्राकृतिक खेती केवल एक कृषि तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की भारतीय पद्धति है। वे इसे किसानों की लागत घटाने, आय बढ़ाने और उन्हें बाहरी निर्भरता से मुक्त करने का सशक्त माध्यम मानते हैं। साथ ही, यह देशवासियों को रसायन-मुक्त, विषरहित भोजन उपलब्ध कराने का मार्ग है। यही कारण है कि प्राकृतिक खेती को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा गया है।

प्राकृतिक खेती की कार्यप्रणाली सरल, स्वदेशी और प्रभावशाली है। इसमें गौशालाओं को केवल संरक्षण केंद्र नहीं, बल्कि कृषि आदानों के उत्पादन के आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। गोबर और गोमूत्र से तैयार जीवामृत, बीजामृत और पंचगव्य जैसे प्राकृतिक इनपुट मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करते हैं और भूमि की उर्वरता को दीर्घकालिक रूप से बढ़ाते हैं। पलवार (मल्चिंग) जैसी तकनीकें मिट्टी की नमी बनाए रखती हैं, जल संरक्षण में सहायक होती हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से फसलों की रक्षा करती हैं। इन उपायों से खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आती है, जिससे शून्य बजट प्राकृतिक खेती का लक्ष्य व्यवहारिक रूप से संभव होता है।

सहकारिता से समृद्धि और संस्थागत शक्ति

प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन बनाने में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके विजन 'सहकारिता से समृद्धि' के तहत, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को संगठित किया जा रहा है एवं किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सशक्त बनाया जा रहा है ताकि छोटे किसानों को न केवल सस्ती दरों पर प्राकृतिक खाद-बीज मिल सकें, बल्कि उनके विषमुक्त उत्पादों को उचित बाजार और लाभकारी मूल्य भी प्राप्त हो सके। गौ-आधारित प्राकृतिक खेती और सहकारिता का मेल ही ग्रामीण समृद्धि का नया मार्ग है।

प्राकृतिक खेती का महत्व केवल खेत तक सीमित नहीं है; इसका सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य और जीवनशैली से है। आज जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, जिनका एक बड़ा कारण रासायनिक अवशेषों से युक्त भोजन है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त शुद्ध और विषमुक्त अन्न पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है, रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा योग और आयुष को वैश्विक पहचान दिलाना इसी समग्र स्वास्थ्य दृष्टि का हिस्सा है। योग, प्राणायाम और संतुलित दिनचर्या तभी पूर्ण लाभ देती है जब भोजन भी शुद्ध और प्राकृतिक हो। प्राकृतिक खेती, स्वस्थ भोजन और योग—तीनों मिलकर स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं।

प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का व्यावहारिक मंत्र—'एक एकड़, एक मौसम'—किसानों के लिए प्रेरणास्रोत है। छोटे स्तर पर प्रयोग कर किसान बिना जोखिम उठाए परिणाम देख सकता है और फिर धीरे-धीरे विस्तार कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, आदानों की उपलब्धता और बाजार से जोड़ने के लिए मजबूत संस्थागत समर्थन दिया जा रहा है। किसान उत्पादक संगठन (FPOs) इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को सामूहिक शक्ति प्राप्त हो रही है। यह भी

उल्लेखनीय है कि महिला किसान इस परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

इस संपूर्ण प्रयास में गौ-सेवा का स्थान केंद्रीय है। गौवंश का संरक्षण और संवर्धन केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण रोजगार और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी की दृष्टि में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और सतत विकास सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम है। मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी की इस दूरदर्शी सोच को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में प्राकृतिक खेती, गौ-संवर्धन और किसान कल्याण को समन्वित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि मिट्टी, किसान और उपभोक्ता—तीनों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

गौ-आधारित प्राकृतिक खेती, भारतीय जीवनदृष्टि का पुनर्जागरण

गौ-आधारित प्राकृतिक खेती केवल कृषि सुधार की पहल नहीं, बल्कि भारतीय जीवनदृष्टि का पुनर्जागरण है। गौमाता और मिट्टी की रक्षा के अपने सांस्कृतिक दायित्व को निभाते हुए, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ भोजन, संतुलित जीवनशैली और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। यही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित, आत्मनिर्भर और स्वस्थ भारत के स्वप्न को साकार करने का सशक्त मार्ग है।

• श्री राजेन्द्र शुक्ल

(पिछले पृष्ठ का शेष)

खेल और सहकारिता में हुई....

सहायता प्रदान की, जिससे ऋण वितरण दोगुना होकर 600 करोड़ रुपये से अधिक हुआ। उन्होंने बताया कि 4518 PACS के माध्यम से PMKSK अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 24.66 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किया गया। Rupay KCC कार्ड एवं माइक्रो एटीएम से वस्तु ऋण की सुविधा भी प्रारंभ की गई है।

सहकारिता में नवाचार और रोजगार सृजन

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि 'एमपी चीता' सहकारी बीज ब्रांड की शुरुआत, CPPP मॉडल के माध्यम से निजी निवेश और सहकारी क्षेत्र का समन्वय तथा दुग्ध उत्पादन में NDDB के साथ सहयोग से किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। दुग्ध उत्पादकों को बेहतर मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि GIS-2025 में CPPP मॉडल प्रारंभ कर सहकारी समितियों को निजी निवेश से जोड़ा गया। धान, नेपियर घास सहित विभिन्न फसलों में व्यावसायिक भागीदारी प्रारंभ की गई है।

IBPS के माध्यम से भर्ती

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि सहकारी संस्थाओं के कुशल संचालन हेतु मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। IBPS के माध्यम से PACS, जिला सहकारी बैंकों एवं अपेक्स बैंक में हजारों पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है। उन्होंने बताया कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत 5,200 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण कर सहकारी कर्मचारियों को आधुनिक बैंकिंग, डिजिटल प्रणाली और प्रबंधन कौशल में दक्ष बनाया गया है।

डेयरी विकास: पशुपालकों की आय में स्थायी वृद्धि

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि डेयरी क्षेत्र में NDDB के सहयोग से 2,200 से अधिक दुग्ध सहकारी समितियों को सक्रिय किया गया है। दुग्ध संग्रह, गुणवत्ता परीक्षण और विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने बताया कि दूध के खरीद मूल्य में 2.50 से 8.50 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि से पशुपालकों की आय में सीधा लाभ हुआ है। इंदौर में मिल्क पाउडर प्लांट के शुभारंभ से प्रदेश की डेयरी क्षमता को नई मजबूती मिली है।

युवा सहभागिता एवं रोजगारोन्मुख सहकारिता

मंत्री श्री सारंग ने आगामी कार्य योजना की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी वर्षों में सहकारिता के विस्तार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में युवाओं की सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों के उपयोग से छोटे उद्योग, खेल, पर्यटन और व्यायाम आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

डिफॉल्टर किसानों के लिये लायेंगे ओटीएस की योजना

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु ऑनलाइन केसीसी आवेदन, एकीकृत साख सीमा तथा नकद-वस्तु ऋण की बाध्यता समाप्त करने जैसे सुधार प्रस्तावित हैं। सभी PACS में ई-PACS के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं और SMS सूचना अनिवार्य की जाएगी। उन्होने बताया कि कमजोर जिला सहकारी बैंकों को आर्थिक सहायता देकर 0% ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। डिफॉल्टर किसानों को मुख्यधारा में लाने हेतु एकमुश्त समझौता योजना तथा आर्थिक अनियमितताओं से प्रभावित किसानों को जांच अवधि में राहत देने की व्यवस्था हेतु न्याय योजना प्रस्तावित है।

सीपीपीपी मॉडल का करेंगे विस्तार

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के अनुरूप राज्य की सहकारिता नीति में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। जनवरी 2026 में IBPS के माध्यम से 2000 से अधिक पदों पर भर्ती एवं सतत प्रशिक्षण की योजना है। उन्होंने कहा कि CPPP मॉडल के विस्तार से सहकारिता में निजी निवेश और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 अंतर्गत उत्कृष्ट संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाएगा तथा जिला सहकारी बैंकों में NEFT/RTGS, QR कोड एवं इंटरनेट बैंकिंग जैसी आधुनिक तकनीकी सुविधाएं लागू की जाएंगी।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल

कैलेण्डर 2026

जनवरी 2026

रवि		4	11	18	25
सोम		5	12	19	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरु	1	8	15	22	29
शुक्र	2	9	16	23	30
शनि	3	10	17	24	31

फरवरी 2026

रवि	1	8	15	22
सोम	2	9	16	23
मंगल	3	10	17	24
बुध	4	11	18	25
गुरु	5	12	19	26
शुक्र	6	13	20	27
शनि	7	14	21	28

मार्च 2026

रवि	1	8	15	22	29
सोम	2	9	16	23	30
मंगल	3	10	17	24	31
बुध	4	11	18	25	
गुरु	5	12	19*	26	
शुक्र	6	13	20*	27	
शनि	7	14	21	28	

अप्रैल 2026

रवि		5	12	19	26
सोम		6	13	20*	27
मंगल		7	14*	21	28
बुध	1†	8	15	22	29
गुरु	2	9	16	23	30
शुक्र	3	10	17	24	
शनि	4	11	18	25	

मई 2026

रवि	31	3	10	17	24
सोम		4	11	18	25
मंगल		5	12	19	26
बुध		6	13	20	27
गुरु		7	14	21	28
शुक्र	1	8	15	22	29
शनि	2	9	16	23	30

जून 2026

रवि		7	14	21	28
सोम	1	8	15	22	29
मंगल	2	9	16	23	30
बुध	3	10	17*	24	
गुरु	4	11	18	25	
शुक्र	5	12	19	26	
शनि	6	13	20	27	

जुलाई 2026

रवि		5	12	19	26
सोम		6	13	20	27
मंगल		7	14	21	28
बुध	1	8	15	22	29
गुरु	2	9	16	23	30
शुक्र	3	10	17	24	31
शनि	4	11	18	25	

अगस्त 2026

रवि	30	2	9	16	23
सोम	31	3	10	17	24
मंगल		4	11	18	25
बुध		5	12	19	26
गुरु		6	13	20	27
शुक्र		7	14	21	28
शनि	1	8	15	22	29

सितम्बर 2026

रवि		6	13	20	27
सोम		7	14*	21	28
मंगल	1	8	15	22	29
बुध	2	9	16	23	30
गुरु	3	10	17	24	
शुक्र	4	11	18	25	
शनि	5	12	19	26	

अक्टूबर 2026

रवि		4	11	18	25
सोम		5	12	19	26*
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरु	1	8	15	22	29
शुक्र	2	9	16	23	30
शनि	3	10	17	24	31

नवम्बर 2006

रवि	1	8	15	22	29
सोम	2	9	16	23	30
मंगल	3	10	17	24	
बुध	4	11	18	25	
गुरु	5	12	19	26	
शुक्र	6	13	20	27	
शनि	7	14	21	28	

दिसम्बर 2026

रवि		6	13	20	27
सोम		7	14	21	28
मंगल	1	8	15	22	29
बुध	2	9	16	23	30
गुरु	3	10	17	24	31
शुक्र	4	11	18	25	
शनि	5	12	19	26	

शासकीय अवकाश - 26 जनवरी- गणतंत्र दिवस, 1 फरवरी - संत रविदास जयन्ती, 15 फरवरी - महाशिवरात्रि, 3 मार्च - होली, 19 मार्च - गुडी पड़वा, 20 मार्च - चैती चांद, 21 मार्च - ईद-उल-फित्र, 2 7 मार्च - रामनवमी, 31 मार्च - महावीर जयन्ती, 1 अप्रैल - बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी, 3 अप्रैल - पुण्य शुक्रवार (गुड फ्रायडे), 14 अप्रैल - डॉ. अम्बेडकर जयन्ती/वैशाखी, 20 अप्रैल - परशुराम जयन्ती, 1 मई - बुद्ध पूर्णिमा, 27 मई - ईदुज्जुहा, 17 जून - महाराणा प्रताप जयन्ती/छत्रसाल जयन्ती, 26 जून - मोहर्रम, 15 अगस्त - स्वतंत्रता दिवस, 26 अगस्त - मिलाद-उन-नबी, 28 अगस्त - रक्षाबन्धन, 4 सितम्बर - जन्माष्टमी, 14 सितम्बर - गणेश चतुर्थी, 2 अक्टूबर - गाँधी जयन्ती, 20 अक्टूबर - दशहरा (विजयादशमी), 26 अक्टूबर - महर्षि वाल्मीकी जयन्ती, 8 नवम्बर - दीपावली, 9 नवम्बर - गोवर्धन पूजा, 15 नवम्बर - राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस (भगवान बिरसा मुण्डा जयन्ती), 24 नवम्बर - गुरुनानक जयन्ती, 25 दिसम्बर - क्रिसमस

* कोषागारों एवं उप-कोषागारों के लिए यह छुट्टियाँ नहीं हैं. † केवल कोषागारों एवं उप-कोषागारों के लिये यह छुट्टी है.

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।